



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 7 नवम्बर, 2000/16 कार्तिक, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला-9, 20 अक्तूबर, 2000

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) कमनाला-25194-25200.—यह कि श्री बलदेव सिंह, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नुरपुर, जिला कांगड़ा को उपायुक्त, कांगड़ा द्वारा आदेश सं० के० जी० आर०-ई०-(14) 22/91, दिनांक 26-8-2000 द्वारा निम्नलिखित आरोपों में संलिप्त पाए जाने के कारण उनके पद से निलम्बित किया गया :—

1. यह कि रास्ता निर्माण पी० डब्ल्यू० सड़क नरेन्द्र के घर से जोगिन्द्र के घर तक विकास में जनसहयोग के अन्तर्गत मु० 92,600/- रु० की स्वीकृत धनराशि में से प्रधान द्वारा 90,800/- रु० की राशि चार किशतों में खण्ड विकास अधिकारी नुरपुर के कार्यालय से प्राप्त की। इस कार्य हेतु प्रधान द्वारा मु० 1,26,404/- रु० का व्यय दर्शाया है परन्तु तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता नुरपुर की एम० बी० नं०-6439 में उपरोक्त रास्ता निर्माण का मूल्यांकन मु० 1,02,548/- रु० पाया गया है तथा इसे स्वीकृत अनुदान तक सीमित किया गया। इस प्रकार श्री बलदेव सिंह ने स्वीकृत धनराशि से

अधिक मु० 35,604/- रु० का अनाधिकृत रूप से व्यय दर्शाते हुए सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया है।

2. और यह कि प्रधान विकास कार्यों पर किए गए मासिक व्यय का अनुमोदन पंचायत व ग्राम सभा से प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं जिस कारण वे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 18 (3) व 27 (3) के उल्लंघना के दोषी पाए गए हैं। उक्त प्रधान द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय, जसूर के 3 कमरों के निर्माण के समय मई, 1998 में उठाए गए लगभग 1000 पत्थरों को वापिस किए जानें के आश्वासन के बाद भी मुख्याध्यापक को न लौटा कर उक्त नियमों की अवहेलना के दोषी पाए गए हैं।
3. यह कि विकास में जन सहयोग के अन्तर्गत मु० 1,63,000/- रु० राजकीय उच्च विद्यालय, जसूर के तीन कमरों के निर्माणार्थ स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 16-9-98 तक मु० 1,30,000/- रु० की राशि उक्त प्रधान को अदा की जा चुकी है परन्तु लगभग दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी प्रधान द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण न करवा कर अपने दायित्वों के प्रति उपेक्षा तथा उदासीनता का प्रमाण दिया है।
4. ये कि विकास में जनसहयोग योजना के अन्तर्गत सुरेन्द्र के घर से चरणजीत के घर तक पक्का रास्ता निर्माण हेतु मु० 82,200/- रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया जिसमें से खण्ड विकास अधिकारी, नूरपुर द्वारा 26-11-98 तक मु० 65,600/- रुपये की अदायगी की जा चुकी है। इस कार्य पर प्रधान द्वारा 64,925/- रु० का व्यय दर्शाया गया है जबकि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इस कार्य का मूल्यांकन मु० 57,616/- रु० आंका गया है। रास्ते में कंकरीट कार्य किया जाना अभी भी शेष है। स्पष्ट है कि प्रधान द्वारा प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग किया गया है।
5. यह कि विकास में जन सहयोग के अन्तर्गत कुलदीप के घर से सुभाष के घर तक लिक रोड निर्माणार्थ मु० 84,800/- रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया था जिसमें से खण्ड विकास अधिकारी नूरपुर द्वारा दो किशतों की अदायगी मु० 47,500/- रु० प्रधान को की गई परन्तु दिनांक 7-12-98 तक केवल मु० 32,700/- रु० का ही व्यय किया गया। सड़क का कार्य अधूरा है। प्रधान द्वारा यह कार्य 16 मास की अवधि व्यतीत होने तक भी पूर्ण न करना करके कर्तव्य के प्रतिलापत्वाही कर धन के दुरुपयोग की पुष्टि करता है।
6. यह कि विकास में जनसहयोग योजना के अन्तर्गत निर्माण कुआँ जसूर हेतु मु० 1,00,000/- रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया जिसमें से खण्ड विकास अधिकारी, नूरपुर द्वारा 12-11-98 तक मु० 50,000/- रु० की दो किशतें अदा की गई। निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है।

और यह कि उपरोक्त आरोपों की वास्तविकता जानने हेतु राज्य सरकार ने नियमित/वैधानिक जांच संचालित करने का जनहित में निर्णय लिया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 में प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए श्री बलदेव सिंह (प्रधान निलंबित), ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड, नूरपुर, जिला कांगड़ा के विरुद्ध कथित आरोपों में संलिप्तता पाए जाने के कारण जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा को जांच अधिकारी तथा पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड नूरपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। जांच अधिकारी ने अनुरोध है कि वे उपरोक्त आरोपों की जांच एक माह के भीतर-भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करें। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी पंचायत का रिकार्ड प्रस्तुत करने के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। श्री बलदेव सिंह, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि वे जांच अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

आदेश द्वारा,

एस० राय,

आयुक्त एवं सचिव (पंचायत)।

कार्यालय सचिव नगर पंचायत कोटखाई

अधिसूचना

कोटखाई, 31 अक्तूबर, 2000

संख्या 288-289.—राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या यू0 डी0-एफ0 (4)-3/98-III दिनांक 3-8-2000 के द्वारा हिमाचल प्रदेश गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1979 (1979 का 19) की धारा के खण्ड (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सचिव, नगर पंचायत कोटखाई एतद्द्वारा नगर पंचायत कोटखाई के क्षेत्राधिकार के अन्दर के निम्न क्षेत्रों को गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित करता हूँ:—

क्र० सं० सम्बन्धित क्षेत्र	सीमायें
1	3
1. वार्ड नं० 1 छोल गांव	छोल सम्पूर्ण गांव
2. वार्ड नं० 5 गिरी वार्ड	वार्ड नं० 5 में नगर पंचायत कोटखाई के शौचालय से गिरी पुल तक की बस्ती तथा बैकरी से रणू राम भवन तक का एरिया ।
3. वार्ड नं० 7 तहसील, पुलिस व वन परिसर ।	बस स्टैंड से बाजार की ओर आने वाली सड़क के पीछे, वन परिसर व पुलिस परिसर में नीचे की बस्ती ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

सचिव,

नगर पंचायत कोटखाई,
जिला शिमला (हि० प्र०) ।

